for the renovation and technological upgradation of the Indian Iron and Steel Company at Burnpur;

(b) if so, what is the estimated cost for this renovation and upgradation;

(c) what are the benefits likely to be accrued by this technological upgradation;

(d) whether there are similar proposals on at the anvil for upgrading other public sector steel plants in the country; and

(e) if so, what are the names of these steel plants and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) and (b) Yes, Sir. An integrated proposal for the renovation and technological upgradation of the Burnpur Works of IISCO has been formulated at an estimated cost of Rs. 931.5 crores (third quarter, 1983 prices) and is under the consideration of the Government.

(c) The benefits likely to be accrued by this technological upgradation are—improvement in the quality of raw materials, intermediates and finished products; reduction in specific consumption of raw materials and energy; conservation of scarce raw materials like metallurgical coal; improvement in productivity and in overall viability; and restoration of capacity to 1 MT per year.

(d) and (e) Yes, Sir. Schemes for the renovation and technological upgradation of the steel plants in Durgapur and Rourkela have been prepared and are under various stages of consideration of Government. Similar schemes for the Bhilai and Bokaro steel plants are also under preparation.

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनः सक्रिय किया जाना

555. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनः सक्रिय करने और इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए क्या नवीनतम कदम उठाये गये हैं; और

(ख) पंजाब, जम्मू और कश्मीर और असम में सक्रिय विघटनकारी तत्वों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार द्वारा कौन से सुझाव और कार्यक्रम किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : (क) इस समय गठित राष्ट्रीय एकता परिषद एक प्रतिनिधि निकाय है जिसके सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री, विपक्षी दलों के नेता और जनता के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। परिषद का सितम्बर, 1980 में पुनर्गठन किया गया था और उसके बाद नवम्बर, 1980 और जनवरी, 1984 में उसकी बैठकें हो चुकी हैं। इसकी तीन समितियों की भी समय-समय पर बैठकें होती रही हैं।

(ख) सरकार पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा असम समेत भारत के विभिन्न भागों की घटनाओं से निरन्तर सम्पर्क में रहती है और राष्ट्रीय एकता तथा भावनात्मक एकता बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उपाय करती रही है। सरकार विभिन्न उपाय कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विखण्डनकारी और और विघटनकारी प्रवृत्तियों जैसे साम्प्रदायिकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और भाषाईवाद पर नियंत्रण है तथा वह राष्ट्र है

के सभी भागों में साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के कार्य में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं।

हरियाणा में बदरपुर खदानों का बन्द किया जाना

556. श्री नत्था सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके बड़े पट्टे धारियों द्वारा हरियाणा के गुड़गांव जिले में बन्धवारी ग्राम पंचायत में बदरपुर खदानों को 4 जून, 1984 को बन्द कर दिया गया था, जिससे खनिक बेरोजगार हो गये है और अल्प कालिक ठेकेदारी द्वारा निवेशित पूंजी का नुकसान हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाय करने और इस प्रकार राजस्व के नुकसान को बचाने का विचार रखती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सातवीं योजना में क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए कदम

557. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि एक ओर चार विकसित राज्यों में, अर्थात् पंजाब (2227 रुपए), महाराष्ट्र (2027 रुपए), हरियाणा (1867 रुपए) और गुजरात (1623 रुपए,) प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है दूसरी ओर पिछड़े राज्य अर्थात् बिहार (715 रुपए) उड़ीसा (843 रुपए), मध्य प्रदेश (877 रुपए) और उत्तर प्रदेश (994 रुपए) प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पहले केन्द्र-राज्य सहायता का अनुपात, क्रमश: 60.1 और 39.9 प्रतिशत था, लेकिन अब यह अनुपात 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत हो गया है और 20 प्रतिशत सहायता पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिससे केन्द्र की सहायता कम हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए सातवीं योजना में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्रश्न में बताए गए 4 पिछड़े राज्यों और 4 विकसित राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल राज्य देशीय उत्पाद पिछले वर्षों में बढ़ा है, जैसा कि संलग्न विवरण से भी देखा जा सकता है।

(ख) विभिन्न योजनाओं में कुल राज्य योजना परिव्यय और केन्द्रीय सहायता का अनुपात नीचे बताए अनुसार है :—

पहली योजना	61.8 प्रतिशत
दूसरी योजना	50.8 प्रतिशत
तीसरी योजना	60.4 प्रतिशत
चौथी योजना	46.0 प्रतिशत
पांचवी योजना	39.8 प्रतिशत
छठी योजना	31.6 प्रतिशत